Machine Translated by Google

आरयू-49-03-0004-011221/एफएक्यू

PRESS INFORMATION BUREAU
(Research Unit)
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

01 दिसम्बर 2021

प्रसंग

जलवायु परिवर्तन1 हमारे समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है। हाल की घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी बढ़ती संवेदनशीलता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कृषि को प्रभावित करने से लेकर खाद्य सुरक्षा को और अधिक खतरे में डालने से लेकर समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों के त्वरित कटाव, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती तीव्रता, प्रजातियों के विलुप्त होने और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार तक होंगे।

परिचय

भारत के प्रारंभिक राष्ट्रीय संचार के एक भाग के रूप में जल संसाधन, कृषि, वन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की भेद्यता मूल्यांकन और अनुकूलन अध्ययन किए गए थे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के लिए।

इसके अलावा, जून 2007 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विशेषज्ञ समिति ने छह क्षेत्रों, अर्थात् जल संसाधन, कृषि, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और जलवायु मॉडलिंग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया। तब विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें तैयार की गईं और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए।

1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) क्या है ?

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) 30 जून 2008 को प्रधान मंत्री द्वारा जारी की गई थी ।3 यह एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है जिसका उद्देश्य देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम बनाना और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाना है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करने के लिए उच्च विकास दर बनाए रखना आवश्यक है।

आठ "राष्ट्रीय मिशन" हैं जो राष्ट्रीय कार्य योजना का मूल हैं।
वे जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और शमन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।‖4

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2822162/
2 https://unfccc.int/resource/docs/natc/indnc1.pdf
3 https://pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=44098
4 https://vikaspedia.in/energy/policy-support/environment-1/climate-change

Machine Translated by Google

2. जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन से मिशन आते हैं ?

आठ राष्ट्रीय मिशन हैं5 जलवायु परिवर्तन पर:

1. राष्ट्रीय सौर मिशन
2. उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
3. सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
6. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
7. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

3. इस योजना के सिद्धांत क्या हैं?

एनएपीसीसी6 के सिद्धांत हैं:

- समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से गरीबों की रक्षा करना,
  जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील
- पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन उद्देश्यों को प्राप्त करना

- अंतिम-उपयोग मांग-पक्ष प्रबंधन के लिए कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियाँ
- के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की व्यापक और त्वरित तैनाती
  अनुकूलन और शमन
- सतत विकास के लिए नए और अभिनव बाजार, नियामक और स्वैच्छिक तंत्र

- अद्वितीय संबंधों के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन - नागरिक समाज, एलजीयू और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ

4. राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM) क्या है?

एनएसएम को जनवरी 20107 में लॉन्च किया गया था , देश भर में यथाशीघ्र सौर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नीतिगत स्थितियां बनाकर, भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से।

एनएसएम का प्रारंभिक लक्ष्य 2022 तक 20 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित करना था। इसे 2015 की शुरुआत में 100 गीगावॉट तक बढ़ाया गया था। मिशन के तहत कई सुविधाजनक कार्यक्रमों और योजनाओं ने ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को वर्ष 2010 में 25 मेगावाट से बढ़ा दिया है। 31 अक्टूबर 2020 तक 11 से लगभग 36.32 गीगावॉट। अतिरिक्त 58.31 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता वर्तमान में स्थापना/निविदा प्रक्रिया के तहत है।

5 https://dst.gov.in/climate-change-programme
6 http://moef.gov.in/wp-content/uploads/2018/07/CC_ghsh.pdf
7 https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1685046

Machine Translated by Google

5.राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय सौर मिशन8 का उद्देश्य इसका उद्देश्य यथाशीघ्र देश भर में इसके प्रसार के लिए नीतिगत स्थितियां बनाकर भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। मिशन तीन चरण का दृष्टिकोण अपनाता है, चरण 1 (2012 तक -
13), चरण 2 (2013 - 17) और चरण 3 (2017 - 22)। मिशन का तात्कालिक उद्देश्य देश में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों स्तरों पर सौर प्रौद्योगिकी के प्रवेश के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

6. राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) क्या है?

एनएमईईई का लक्ष्य अनुकूल विनियामक और नीति व्यवस्था बनाकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना है और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में अभिनव और टिकाऊ व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। यह मिशन 2011.9 से कार्यान्वित है

एनएमईईई में ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए चार पहल शामिल हैं10:

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी)
- ऊर्जा दक्षता के लिए बाज़ार परिवर्तन (MTEE)
- ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी)
- ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा (FEEED)

7. सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन क्या है?

सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन को जून 2010 में प्रधान मंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।11

मिशन के प्रमुख प्रदेय में शामिल हैं:

- टिकाऊ आवास मानकों का विकास जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के साथ-साथ मजबूत विकास रणनीतियों को जन्म देता है
- व्यापक रूप से संबोधित करने वाली शहर विकास योजनाओं की तैयारी अनुकूलन और शमन संबंधी चिंताएँ
- व्यापक गतिशीलता योजनाओं की तैयारी जो शहरों को दीर्घकालिक, ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी परिवहन योजना बनाने में सक्षम बनाती है
- मिशन से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण

8. राष्ट्रीय जल मिशन क्या है?

एक राष्ट्रीय जल मिशन12 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करेगा जो पानी के संरक्षण, बर्बादी को कम करने और राज्यों के भीतर और भीतर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा और विभिन्न विनियामक तंत्रों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा।

---

8 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन - विकासपीडिया

9 https://vikaspedia.in/energy/policy-support/energy-efficiency/national-mission-for-enhanced-energy-efficiency

10 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1744431

11 http://cpheo.gov.in/cms/national-mission-on-sustainable-habitat.php

12 http://nwm.gov.in/

Machine Translated by Google

अधिकार और मूल्य निर्धारण। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि शहरी क्षेत्रों की पानी की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के माध्यम से पूरा किया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों वाले तटीय शहरों की पानी की जरूरतों को नई और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से पूरा किया जाए। निम्न तापमान अलवणीकरण प्रौद्योगिकियाँ जो समुद्र के पानी के उपयोग की अनुमति देती हैं।

NWM13 ने पाँच लक्ष्यों की पहचान की है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटा बेस और इसका मूल्यांकन
  जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- जल संरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण के लिए नागरिक एवं राज्य के कार्यों को बढ़ावा देना

- अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया
- जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत की वृद्धि • बेसिन स्तर पर एकीकृत
जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना

9. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है?

यह विशेष मिशन हिमालय के ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने और हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।14

एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र चार प्रकार की राष्ट्रीय क्षमताओं के तेजी से सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो निम्न से संबंधित हैं:

- मानव और ज्ञान क्षमताएं • संस्थागत क्षमताएं •
साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और
शासन की क्षमताएं • प्रकृति की शक्तियों और कार्यों के बीच संतुलन के लिए निरंतर स्व-शिक्षा

मानवता

मिशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है

- हिमालय के ग्लेशियर और संबंधित जलवैज्ञानिक परिणाम
- जैव विविधता संरक्षण और संरक्षण • वन्यजीव संरक्षण और
सुरक्षा • पारंपरिक ज्ञान समाज और उनकी आजीविका और

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए योजना बनाना

10. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है?

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय हरित मिशन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी India15(GIM) एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में।

जीआईएम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के संदर्भ में "हरियाली" 16 रखता है। हरियाली का अर्थ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कार्बन पृथक्करण और भंडारण (जंगलों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जल विज्ञान सेवाओं और जैव विविधता को बढ़ाना है; साथ ही ईंधन, चारा, छोटी लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) जैसी अन्य प्रावधान सेवाएं।

मिशन का लक्ष्य अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है, जिससे मदद मिलेगी:

13http://nwm.gov.in/
14http://dst.gov.in/sites/default/files/NMSHE_जून_2010.pdf
15https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103978
16http://www.jkfest.gov.in/pdf/gim/GIM_Mission-Document-1.pdf

Machine Translated by Google

- सतत रूप से प्रबंधित वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बन सिंक को बढ़ाना
- बदलती जलवायु के प्रति संवेदनशील प्रजातियों/पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकूलन
- वनों पर निर्भर समुदायों का अनुकूलन

मिशन के उद्देश्य हैं:

- 5 मिलियन हेक्टेयर वन/गैर-वन भूमि पर वन/वृक्ष आवरण में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार
  अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन आवरण (कुल 10 मिलियन हेक्टेयर)
- जैव विविधता, जल विज्ञान सेवाओं और कार्बन सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार
  10 मिलियन हेक्टेयर के उपचार के परिणामस्वरूप ज़ब्ती
- में रहने वाले लगभग 30 लाख परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय में वृद्धि
  जंगलों के आसपास • वर्ष

2020 में वार्षिक CO2 अवशोषण में 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि

11. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है?

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन17 (एनएमएसए) इसे वर्ष 2014-15 से चालू कर दिया गया है, इसका उद्देश्य स्थान विशिष्ट एकीकृत/ मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु लचीला बनाना है; मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय; व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन; कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और वर्षा आधारित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना।

कृषि जल प्रबंधन (एफडब्ल्यूएम) को 2014-15 के दौरान एनएमएसए के घटकों में से एक के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रौद्योगिकियों, कुशल जल अनुप्रयोग और वितरण प्रणाली, माध्यमिक भंडारण आदि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना था। इन गतिविधियों को 2015-16 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)' घटक के तहत शामिल किया गया है ।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत घटकों में से एक है। एसएचएम का उद्देश्य जैविक खाद और जैव-उर्वरक के साथ-साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना है।

मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार, मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किसानों को मिट्टी परीक्षण आधारित सिफारिशों में सुधार के लिए मिट्टी और उर्वरक परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना।

देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए फरवरी, 2015 से देश में "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना लागू की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश करेगा।

12. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन क्या है?

जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) एक जीवंत और गतिशील ज्ञान प्रणाली का निर्माण करना चाहता है जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास के उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई को सूचित और समर्थन करेगा।

17https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1556469

Machine Translated by Google

मिशन डिलिवरेबल्स18:

• जलवायु विज्ञान, एस एंड टी क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय-जलवायु मॉडलिंग, कृषि में अनुकूलन रणनीतियों, जल संसाधनों और अन्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों, वैश्विक प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता और क्षेत्रीय उत्सर्जन सूची के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण द्रव्यमान और ताकत वाले कम से कम 10 विषयगत ज्ञान नेटवर्क , भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रासंगिक विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों, कृषि जैव प्रौद्योगिकी का इष्टतम मिश्रण

• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और कृषि, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि जैसे प्रभाव क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों पर उप-मिशन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में कुल 10-12 तकनीकी रिपोर्ट। चरम वायुमंडलीय और समुद्री घटनाओं जैसे मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अन्य तूफान, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर आदि के साथ जलवायु परिवर्तन के संबंधों पर तकनीकी रिपोर्ट भी लाई जाएगी।

• उष्णकटिबंधीय भौतिकी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अलग-अलग जलवायु मॉडल
और भारतीय मानसून-हिमालय संपर्क
• जलवायु परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 50 चेयर प्रोफेसरशिप
• विशेषज्ञता वाले लगभग 200 विशेष रूप से प्रशिक्षित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पेशेवर
ज्ञान क्षेत्र और विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में
• अनुकूलन और शमन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में कम से कम तीन व्यवहार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी

• जलवायु परिवर्तन विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी निगरानी समूह स्वच्छ
कोयला प्रौद्योगिकी, कार्बन पृथक्करण और भंडारण, वाटरशेड प्रबंधन, सटीक कृषि, आवास और निर्माण के लिए अभिसरण प्रौद्योगिकी विकल्प, परिवहन, सौर ऊर्जा सामग्री और उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए एस एंड टी नीति विकसित की जाएगी और एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान के साथ तैनात की जाएगी। विशेषज्ञता का आधार.

• मिशन डिलिवरेबल्स में रणनीतिक ज्ञान मिशन उद्देश्यों के भीतर निहित एनएपीसीसी दस्तावेज़ के स्पष्ट तकनीकी लक्ष्य शामिल होंगे • ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-नीति इंटरफेस पर विषयगत रिपोर्ट, विभिन्न जीडीपी विकास दर पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, कृषि जैव प्रौद्योगिकी
निर्देश • एस एंड टी का विकास आंतरिक प्राथमिकता के माध्यम से पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्रों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों और यूरोपीय संघ जैसे बहुपक्षीय समूहों के साथ सहयोग

संदर्भ

• भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन
• किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
• सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

18https://dst.gov.in/sites/default/files/NMSKCC_mission%20document%201.pdf